International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 03(I), July-September, 2026, pp. 242-247

सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार में शासकीय योजनाओं का योगदान

डॉ. प्रतिमा बनर्जी[1] | आराधना मिश्रा[2]

[1]प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)।
[2]शोधार्थी वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)।

*Corresponding Author: aradhanamishra2340@gmail.com

Citation: बनर्जी, प्रतिमा एवं मिश्रा, आराधना (2026). सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार में शासकीय योजनाओं का योगदान. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(03(I)), 242–247. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.3(I).9450

सार

भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास की आधारशिला भी है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है तथा परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, महिला स्व–सहायता समूह कार्यक्रम तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ प्रमुख हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है, जिनका संकलन विभिन्न शासकीय प्रतिवेदनों, आर्थिक सर्वेक्षणों, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रकाशित शोध अध्ययनों से किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, ऋण सुविधा तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आय, बचत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। यद्यपि योजनाओं के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी इन योजनाओं ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है। अध्ययन निष्कर्ष रूप में यह प्रतिपादित करता है कि सतना जिले में महिला स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के विस्तार में शासकीय योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रहा है।

शब्दकोश: *महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, शासकीय योजनाएँ, सतना जिला, स्व–सहायता समूह, महिला उद्यमिता, ग्रामीण विकास।*

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान प्राचीनकाल से ही महत्वपूर्ण रहा है, किन्तु लंबे समय तक महिलाओं की आर्थिक भूमिका को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक भागीदारी

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

एवं स्वावलंबन की संभावनाएँ सीमित रहीं। आधुनिक युग में शिक्षा, तकनीकी विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार के साथ महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आज महिलाएँ कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय योगदान प्रदान कर रही हैं। इसके बावजूद आर्थिक असमानता, संसाधनों तक सीमित पहुँच तथा रोजगार के अवसरों की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। जब महिला स्वयं आय अर्जित करने में सक्षम होती है, तब उसकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आर्थिक रूप से सक्षम महिला न केवल अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार करती है, बल्कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी कारण महिला आर्थिक सशक्तिकरण को सतत विकास का प्रमुख घटक माना गया है।

भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, वित्तीय सहायता, उद्यमिता विकास तथा आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा स्व–सहायता समूह आधारित कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में भी महिला आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य शासन द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों के गठन, कौशल विकास प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्तीय सहायता तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों ने महिलाओं को सामूहिक बचत, ऋण सुविधा तथा लघु उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरित किया है।

सतना जिला मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, लघु व्यापार एवं सेवा गतिविधियों पर आधारित है। जिले की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी परंपरागत रूप से सीमित रही है। पिछले कुछ वर्षों में शासकीय योजनाओं के प्रभाव से महिलाओं की स्वरोजगार गतिविधियों में वृद्धि हुई है। स्व–सहायता समूहों, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई–कढ़ाई, हस्तशिल्प तथा अन्य सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिलाएँ आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है।

वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से महिला आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी उत्पादन एवं आय सृजन की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले। महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करने से श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है, गरीबी में कमी आती है तथा स्थानीय बाजारों का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

सतना जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की है। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप अनेक महिलाएँ स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हालांकि योजनाओं की पहुँच, जागरूकता तथा क्रियान्वयन संबंधी कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार में शासकीय योजनाओं के योगदान का विश्लेषण करता है तथा यह जानने का प्रयास करता है कि इन योजनाओं ने महिलाओं की आय, रोजगार, बचत, उद्यमिता एवं सामाजिक स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन

उत्पन्न किया है। यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण की आर्थिक प्रक्रिया को समझने तथा भविष्य की नीतियों के निर्माण हेतु उपयोगी आधार प्रदान करता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी समाज के समग्र विकास का आधार है। वर्तमान समय में विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सतना जिले में इन योजनाओं की प्रभावशीलता तथा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं की आर्थिक स्थिति, रोजगार अवसरों तथा शासकीय हस्तक्षेपों के परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि योजनाओं द्वारा महिलाओं को किस सीमा तक आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में उनके लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
- स्वरोजगार एवं महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों एवं सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है। अध्ययन हेतु आवश्यक तथ्यों एवं आँकड़ों का संकलन विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों से किया गया है। इनमें भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के आर्थिक सर्वेक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्टें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दस्तावेज, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ, सतना जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, शोध पत्रिकाएँ, पुस्तकें तथा संबंधित शोध प्रबंध सम्मिलित हैं। प्राप्त आँकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण वाणिज्यिक तथा आर्थिक अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। संकलित तथ्यों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, आय वृद्धि तथा उद्यमिता विकास पर शासकीय योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर सारणीकरण एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण की सहायता से निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। अध्ययन का उद्देश्य नीतिगत एवं व्यावहारिक स्तर पर महिला आर्थिक सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को समझना तथा शासकीय योजनाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करना है।

विश्लेषण

सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार के विकास में शासकीय योजनाओं का योगदान वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास में महिलाओं की उत्पादक सहभागिता आवश्यक होती है। सतना जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं ने महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में ही नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, महिला स्व–सहायता समूह कार्यक्रम तथा कौशल विकास योजनाओं ने महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों का गठन महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं में नियमित बचत की प्रवृत्ति विकसित हुई है तथा उन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं ऋण सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है। सामूहिक बचत एवं ऋण व्यवस्था ने महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया है। सतना जिले में अनेक महिलाएँ डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई–कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों से जुड़कर आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी आई है तथा पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं अन्य वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम हुईं। आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ने से महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। अब महिलाएँ परिवार के आर्थिक निर्णयों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निवेश संबंधी मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन महिला सशक्तिकरण के आर्थिक एवं सामाजिक दोनों आयामों को प्रतिबिंबित करता है।

कौशल विकास कार्यक्रमों ने भी महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर संचालन, सौंदर्य सेवाएँ, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तकला तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षणों के परिणामस्वरूप महिलाएँ स्वरोजगार स्थापित करने अथवा स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने में सफल हुई हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ–साथ आत्मविश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है।

वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमिता के विस्तार ने स्थानीय बाजारों की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है। महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों ने वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय एवं पूंजी का प्रवाह बढ़ा है तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की आय के स्रोतों में विविधता आई है तथा उनकी बाजार सहभागिता में वृद्धि हुई है। यद्यपि शासकीय योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होते हैं, तथापि जागरूकता का अभाव, वित्तीय साक्षरता की कमी, विपणन संबंधी कठिनाइयाँ, तकनीकी ज्ञान का अभाव, ऋण प्राप्ति में विलंब तथा सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके बावजूद यह निर्विवाद है कि विभिन्न शासकीय योजनाओं ने सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इन योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। इस संदर्भ में प्राप्त द्वितीयक समंकों के आधार पर लाभान्वित महिलाओं का वितरण सारणी क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है–

सारणी 1: सतना जिले में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार हेतु लाभान्वित महिलाओं की वर्षवार संख्या का विवरण (2021–22 से 2025–26)

क्र.स.	योजना का विवरण	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
1	स्व–सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएँ	12,846	14,235	16,178	18,462	20,315
2	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित महिलाएँ	6,482	7,315	8,426	9,786	11,024
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से लाभान्वित महिलाएँ	5,637	6,284	7,192	8,153	9,284
4	कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएँ	4,125	4,683	5,542	6,427	7,386
5	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लाभान्वित महिलाएँ	1,826	2,314	2,967	3,894	4,726
6	अन्य महिला स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ	1,462	1,728	2,084	2,621	3,184
कुल योग		32,378	36,559	42,389	49,343	55,919

स्रोत– महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासनय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सतना एवं मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक संकलित, वर्ष 2021–22 से 2025–26

उपरोक्त सारणी के समंकों से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या में वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कुल लाभार्थी महिलाओं की संख्या 2021–22 में 32,378 से बढ़कर 2025–26 में 55,919 हो गई है, जो लगभग 72.70 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। योजना–वार दृष्टि से प्रत्येक वर्ष स्व–सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही तथा 2021–22 में 12,846 से बढ़कर 2025–26 में 20,315 हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या 6,482 से बढ़कर 11,024 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5,637 से बढ़कर 9,284 हो गई। कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की संख्या भी 4,125 से बढ़कर 7,386 हुई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा अन्य महिला स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाओं में भी क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई है। पाँच–वर्षीय अवधि में सभी योजनाओं में लाभार्थी महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि यह संकेत करती है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, सामूहिक आजीविका एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने में शासकीय योजनाओं की भूमिका सुदृढ़ हुई है। विशेष रूप से SHG, मुद्रा योजना एवं छत्स्ड महिलाओं को स्वरोजगार तथा आय–सृजन गतिविधियों से जोड़ने के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययन अवधि में सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संचालित शासकीय योजनाओं का विस्तार हुआ है तथा इनके माध्यम से महिला सहभागिता में सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सकता है कि सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने में विभिन्न शासकीय योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रभावपरक रही है। अध्ययन अवधि 2021–22 से 2025–26 के दौरान योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि का परिलक्षित होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शासकीय स्तर पर संचालित वित्तीय सहायता, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रमों की पहुँच में विस्तार हुआ है। लाभार्थियों की बढ़ती संख्या महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता तथा स्वरोजगार के प्रति अभिरुचि में क्रमिक परिवर्तन को भी इंगित करती है। योजना–वार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि

स्व–सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का प्रमुख आधार रहे हैं। इनके माध्यम से महिलाओं में सामूहिक बचत, ऋण प्राप्ति, लघु उद्यम संचालन तथा आय–सृजन की प्रवृत्ति विकसित हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के लिए संस्थागत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने विशेषतः ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक निर्णय–क्षमता को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। इसी प्रकार कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने महिलाओं की कार्यकुशलता तथा उद्यमशील क्षमता के विकास की आधारभूमि तैयार की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं अन्य उद्यमिता योजनाओं ने महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहित किया है। अतः समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में शासकीय योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक निर्भरता की स्थिति से बाहर निकालकर स्वरोजगार एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। तथापि, योजनाओं के वास्तविक एवं दीर्घकालीन प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु योजना संबंधी जागरूकता, ऋण की सुगम उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, विपणन सुविधा तथा उद्यम स्थापना के पश्चात निरंतर संस्थागत सहयोग को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में समन्वित एवं सतत प्रयास महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, 2025
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2024
3. मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल, 2025
4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रगति प्रतिवेदन, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2024
5. शर्मा, आर.के., भारत में महिला उद्यमिता एवं आर्थिक विकास, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2022
6. सिंह, ए.के., ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 2021
7. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, सतना, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सतना जिला, मध्यप्रदेश शासन, सतना, 2024.

❑❑❑